



<https://doi.org/10.53032/tvcr/2026.v8n1.04>

## उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारण और निराकरण: एक अनुभवजन्य अध्ययन

<sup>1</sup> अजय कुमार सिंह (शोधार्थी)\*

विधि विभाग।

तिलकधारी सिंह स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय,

पीली कोठी, जौनपुर।

Email: ajaysinghsrinet78 @mail.com

<sup>2</sup> प्रोफेसर (डॉ) संतोष कुमार सिंह\*\*

विधि विभाग

तिलकधारी सिंह स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय,

पीली कोठी, जौनपुर

### सारांश(Abstract)

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जो सड़क दुर्घटनाओं की गंभीर समस्या से प्रभावित है। यह अध्ययन राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों की पहचान करता है तथा उनके निराकरण हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है। अध्ययन माध्यमिक डेटा पर आधारित है जिसमें मंत्रालय ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की वार्षिक रिपोर्ट्स, पुलिस रिकॉर्ड तथा अकादमिक अध्ययन शामिल हैं। दो हजार बीस से दो हजार पच्चीस तक के आंकड़ों से स्पष्ट है कि दुर्घटनाओं में निरंतर वृद्धि हुई है। वर्ष दो हजार बाईस में चौवालीस हजार चार सौ तिरासी दुर्घटनाएं दर्ज हुईं जो दो हजार तेईस में बढ़कर छियालीस हजार पांच सौ चौंतीस हो गईं। दो हजार चौबीस में यह संख्या छियालीस हजार बावन तक पहुंची तथा दो हजार पच्चीस में जनवरी से नवंबर तक छियालीस हजार दो सौ तेईस दुर्घटनाएं दर्ज हुईं जिनमें चौबीस हजार सात सौ छिहत्तर से अधिक मौतें हुईं जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। प्रमुख कारणों में अत्यधिक गति से वाहन चलाना लगभग साठ से सत्तर प्रतिशत मामलों में जिम्मेदार रहा है। इसके अतिरिक्त चालक की थकान, खराब सड़क स्थिति तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी महत्वपूर्ण हैं। दोपहिया वाहन तथा पैदल यात्री सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं जहां दोपहिया वाहनों से संबंधित दुर्घटनाएं लगभग उनतालीस प्रतिशत हैं।

# The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 1 (January-March 2026)

यह अध्ययन अनुभवजन्य दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें आंकड़ों के पैटर्न का विश्लेषण कर निराकरण के उपाय सुझाए गए हैं। इनमें बेहतर सड़क इंजीनियरिंग, सख्त कानूनी प्रवर्तन, जन जागरूकता अभियान तथा तकनीकी हस्तक्षेप जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं। उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस का डेटा आधारित रोड सेफ्टी मॉडल कुछ क्षेत्रों में दस से पंद्रह प्रतिशत तक कमी लाया है। अध्ययन का उद्देश्य नीति निर्माताओं को साक्ष्य आधारित सिफारिशें प्रदान करना है ताकि आर्थिक तथा सामाजिक प्रभाव कम हो सके। अनुमानित रूप से सड़क दुर्घटनाओं से राज्य को प्रतिवर्ष पचास हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है जिसमें चिकित्सा व्यय उत्पादकता हानि तथा परिवारों पर प्रभाव शामिल है। प्रभावी उपायों से दो हजार तीस तक पचास प्रतिशत कमी संभव है जैसा कि अन्य राज्यों के सफल मॉडलों से प्रमाणित है। यह अध्ययन सड़क सुरक्षा को बहुआयामी समस्या मानकर एकीकृत दृष्टिकोण की वकालत करता है।

**मुख्य शब्द (Key words):** सड़क दुर्घटना , उत्तर प्रदेश, तकनीक, स्वास्थ्य, अनुभवजन्य

## परिचय(Introduction)

भारत में सड़क दुर्घटनाएं एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या हैं जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश चौबीस करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला राज्य इस समस्या का प्रमुख केंद्र है जहां राष्ट्रीय औसत से अधिक दुर्घटनाएं होती हैं। दो हजार बाईस में पूरे भारत में चार लाख इकसठ हजार तीन सौ बारह दुर्घटनाएं दर्ज हुईं जिनमें उत्तर प्रदेश का योगदान नौ प्रतिशत से अधिक था तथा मृत्यु दर में यह राज्य शीर्ष पर रहा। **प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी** जैसे शहरों में शोधार्थी द्वारा सड़क दुर्घटना और उसके बाद क्षति को अनुभव किया गया है।

समस्या की गंभीरता को समझने के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दुर्घटनाएं केवल जान माल की हानि नहीं करतीं बल्कि आर्थिक बोझ भी बढ़ाती हैं। अनुमान के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से देश को सकल घरेलू उत्पाद का तीन से पांच प्रतिशत नुकसान होता है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान करना है जैसे अत्यधिक गति खराब मौसम वाहन की खराब स्थिति तथा मानवीय त्रुटियां। साथ ही वर्तमान नीतियों का मूल्यांकन कर सुधार सुझाना है। संभावित क्षेत्रों में सड़क उपयोगकर्ताओं का व्यवहार तकनीकी हस्तक्षेप तथा नीतिगत बदलाव शामिल हैं। अध्ययन वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है जो **मंत्रालय ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज** उत्तर प्रदेश पुलिस तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त हैं। यह अध्ययन सड़क सुरक्षा में सुधार लाने में योगदान देगा विशेषकर युवा आबादी के संरक्षण में क्योंकि अठारह से पैंतालीस वर्ष आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है।

## साहित्य समीक्षा (literature review)

सड़क दुर्घटनाएँ भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश जैसे घनी आबादी वाले राज्य में। विभिन्न अध्ययनों ने इनके कारणों, पैटर्न और निराकरण पर प्रकाश डाला

# The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 1 (January-March 2026)

है। गुरुराज (2008) ने भारत में सड़क दुर्घटनाओं के रुझानों का विस्तृत विश्लेषण किया, जिसमें ओवरस्पीडिंग और शराब का सेवन प्रमुख मानवीय कारण बताए गए। अध्ययन के अनुसार, युवा पुरुष सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और दुर्घटनाएँ आर्थिक-सामाजिक बोझ बढ़ाती हैं।

उत्तर प्रदेश पर केंद्रित शोधों में, **जायसवाल एट अल. (2015)** ने ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटनाओं के पैटर्न का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि दोपहिया वाहनों से जुड़ी घटनाएँ लगभग 47% हैं, और ग्रामीण सड़कों पर पैदल यात्रियों तथा दोपहिया चालकों की चोटें गंभीर होती हैं। यह अध्ययन ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के डेटा पर आधारित था, जो दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी प्रमुख समस्या है।

मोहन एट अल. (2018) ने पर्यावरणीय कारकों पर जोर दिया, विशेषकर उत्तर प्रदेश के मानसून और शीतकाल में। **कोहरे, वर्षा और गीली सड़कों** से दुर्घटनाएँ बढ़ जाती हैं, और दोपहिया वाहन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। हाल के अध्ययनों में मौसम-आधारित जोखिम मॉडल विकसित किए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की विविध जलवायु को ध्यान में रखते हैं।

निराकरण के संदर्भ में, सिंह एट अल. (2017) ने जागरूकता अभियानों की प्रभावशीलता पर चर्चा की। **हेलमेट और सीटबेल्ट** के उपयोग से मृत्यु दर 30% तक कम हो सकती है, लेकिन प्रवर्तन की कमी एक बड़ी बाधा है। 360इंफो (2024) ने एआई-आधारित समाधानों पर प्रकाश डाला, जैसे एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स (ADAS), जिनसे दुर्घटनाएँ 20-25% कम हो सकती हैं। ये तकनीकें स्पीड मॉनिटरिंग और रीयल-टाइम अलर्ट प्रदान करती हैं।

यूपी पुलिस की 2025 रणनीति ने डेटा-ड्रिवन मॉडल को सफल बताया, जहां 233 पुलिस स्टेशनों में फोकस्ड हस्तक्षेप से दुर्घटनाएँ और मौतें घटीं। MoRTH की रिपोर्ट्स (2022-2023) से पता चलता है कि ओवरस्पीडिंग 68-71% मौतों का कारण है, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मौतें दर्ज हुईं।

हालाँकि, साहित्य में ग्रामीण बनाम शहरी अंतर पर अपेक्षाकृत कम फोकस है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क डिज़ाइन, आवारा पशु और खराब साइनेज की समस्या अधिक है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक घनत्व और ड्राइवर व्यवहार प्रमुख हैं। यह अध्ययन इन अंतरों को भरने का प्रयास करता है, ताकि क्षेत्र-विशिष्ट नीतियाँ बनाई जा सकें। कुल मिलाकर, साक्ष्य दर्शाते हैं कि बहुआयामी दृष्टिकोण—मानवीय, पर्यावरणीय और तकनीकी—से दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है।

## विधि(Method)

यह अध्ययन पूरी तरह से माध्यमिक डेटा पर आधारित है। शोध के लिए आवश्यक जानकारी विभिन्न विश्वसनीय तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों से एकत्र की गई है। मुख्य डेटा स्रोतों में भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट्स (सड़क दुर्घटनाएँ भारत २०२० से २०२५ तक), उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जारी की गई वार्षिक दुर्घटना रिपोर्ट्स, राज्य परिवहन विभाग के आंकड़े, तथा विभिन्न प्रतिष्ठित अकादमिक पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र शामिल हैं।

डेटा संग्रह की प्रक्रिया व्यवस्थित रूप से की गई। सबसे पहले सभी उपलब्ध वर्षों की MoRTH रिपोर्ट्स को डाउनलोड किया गया तथा उनमें से उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी तालिकाओं तथा ग्राफ्स

# The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 1 (January-March 2026)

को अलग किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट तथा संबंधित सरकारी पोर्टलों से जिला-वार तथा माह-वार दुर्घटना आंकड़े एकत्र किए गए। साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट्स तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सड़क सुरक्षा संबंधी प्रकाशनों से तुलनात्मक जानकारी ली गई।

विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया। प्रारंभिक स्तर पर ट्रेंड एनालिसिस किया गया जिसमें पिछले छह वर्षों में दुर्घटनाओं, घायलों तथा मृतकों की संख्या में परिवर्तन को देखा गया। इसके अतिरिक्त बहु-चर रिग्रेशन मॉडल का प्रयोग किया गया जिसमें दुर्घटनाओं की कुल संख्या को स्वतंत्र चरों जैसे अत्यधिक गति, शराब का सेवन, खराब सड़क स्थिति, मौसम, वाहन प्रकार तथा समय के साथ सहसंबंधित किया गया। डेटा को जिलावार तथा समय-आधारित (सुबह, दोपहर, शाम, रात) वर्गीकृत किया गया ताकि उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों तथा समय की पहचान हो सके। विशेष रूप से लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज तथा आगरा जैसे जिलों पर अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि इनमें दुर्घटनाओं की दर लगातार उच्च रही है।

नमूना आकार बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर दो हजार बीस से दो हजार पच्चीस तक के लगभग दो लाख से अधिक दुर्घटना रिकॉर्ड्स का विश्लेषण किया गया है। ये रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस में दर्ज आधिकारिक मामलों पर आधारित हैं।

नैतिक विचारों का पूरा ध्यान रखा गया है। चूंकि यह अध्ययन केवल माध्यमिक तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा पर आधारित है, इसलिए किसी भी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग या प्रकटीकरण नहीं किया गया है। सभी स्रोतों का उचित उल्लेख किया गया है तथा डेटा की गोपनीयता का पूर्ण सम्मान किया गया है।

अध्ययन की कुछ सीमाएँ भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण सीमा प्राथमिक डेटा (जैसे चालकों, पीड़ितों अथवा गवाहों से साक्षात्कार) की अनुपस्थिति है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में अंडर-रिपोर्टिंग की संभावना रहती है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भविष्य के शोध में प्राथमिक सर्वेक्षण तथा क्षेत्रीय अध्ययन को शामिल करके इन सीमाओं को दूर किया जा सकता है।

## परिणाम (Result)

विश्लेषण से प्राप्त प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं। वर्ष दो हजार बीस में पूरे भारत में तीन लाख बहतर हजार एक सौ इक्यासी सड़क दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं जिनमें से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेरह हजार छह सौ पंचानवे दुर्घटनाएँ हुईं। समय के साथ यह संख्या निरंतर बढ़ती गई। दो हजार पच्चीस के आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक (जनवरी से नवंबर तक) छियालीस हजार दो सौ तेईस से अधिक दुर्घटनाएँ दर्ज हो चुकी हैं जिनमें मृतकों की संख्या सात हजार सात सौ से अधिक तथा घायलों की संख्या तेईस हजार से ऊपर है।

समय के अनुसार देखें तो दोपहर के समय अर्थात् बारह बजे से शाम छह बजे के बीच कुल दुर्घटनाओं का लगभग साठ प्रतिशत हिस्सा दर्ज किया गया है। इसके प्रमुख कारणों में तेज धूप, चालक की थकान तथा अत्यधिक गति शामिल हैं। कारणों के विश्लेषण से पता चलता है कि अत्यधिक गति से वाहन चलाना लगभग सत्तर प्रतिशत मामलों में मौत का मुख्य कारण रहा है। इसके बाद खराब

# The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 1 (January-March 2026)

सड़क स्थिति (छत्तीस प्रतिशत), ट्रैफिक नियमों की अवहेलना तथा वाहनों की खराब स्थिति महत्वपूर्ण हैं।

वाहन प्रकार के अनुसार दोपहिया वाहन सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कुल दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहनों से संबंधित घटनाएँ उनतालीस प्रतिशत हैं जबकि हल्के मोटर वाहन (कार, जीप आदि) अट्ठाईस प्रतिशत तथा भारी वाहन (ट्रक, बस) बाईस प्रतिशत हैं। पैदल यात्री भी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं तथा कुल मौतों में उनका हिस्सा लगभग अठारह प्रतिशत है।

आयु तथा लिंग के आधार पर देखें तो अठारह से पैंतालीस वर्ष की आयु के युवा पुरुष सबसे अधिक प्रभावित हैं। इस आयु वर्ग में कुल मौतों का लगभग छिहत्तर प्रतिशत हिस्सा है। जिला-वार विश्लेषण से पता चलता है कि लखनऊ में पिछले वर्ष की तुलना में पंद्रह प्रतिशत, कानपुर में बारह प्रतिशत तथा वाराणसी में दस प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ये तीन जिले राज्य में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में उभर कर सामने आए हैं।

कुल मिलाकर आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएँ तथा उनसे होने वाली मौतें लगातार बढ़ रही हैं तथा समस्या विशेष रूप से गंभीर हो चुकी है।

## चर्चा( Discussion)

परिणामों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मानवीय त्रुटियाँ सबसे प्रमुख कारक हैं। अत्यधिक गति से वाहन चलाना, शराब का सेवन, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए ड्राइविंग, थकान तथा ट्रैफिक नियमों की अवहेलना जैसी आदतें कुल मौतों के सत्तर प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही सड़क अवसंरचना की कमी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्य मार्गों पर अपर्याप्त लेन, खराब साइनेज, अपर्याप्त स्ट्रीट लाइटिंग, गड्ढे, आवारा पशुओं का आवागमन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क की संकरी चौड़ाई जैसी समस्याएँ दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रही हैं।

पर्यावरणीय कारकों में मौसम की विशेष भूमिका है। मानसून के दौरान गीली सड़कें तथा शीतकाल में घना कोहरा दृश्यता कम करते हैं जिससे दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है। दोपहर के समय (बारह से छह बजे) सबसे अधिक दुर्घटनाएँ होने का कारण तेज धूप, चालक की थकान तथा उच्च गति का संयोजन है।

इन कारणों के निराकरण के लिए बहुआयामी तथा समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। प्रथम, सख्त स्पीड नियंत्रण लागू करना चाहिए। स्पीड कैमरा, स्पीड गन तथा स्वचालित चालान प्रणाली का विस्तार किया जाए। दूसरे, जन जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। स्कूलों, कॉलेजों तथा सामुदायिक स्तर पर नियमित शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट तथा सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों पर जोर दिया जाए। तीसरे, आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जोखिम पूर्वानुमान मॉडल, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम तथा एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जाए। चौथे, नीतिगत स्तर पर आवारा पशुओं के लिए सड़कों के दोनों ओर मजबूत फेंसिंग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा बाधाओं का निर्माण किया जाए।

# The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 1 (January-March 2026)

उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष दो हजार पच्चीस में शुरू की गई योजनाएँ जैसे एकीकृत चालान प्रणाली, डेटा आधारित हॉटस्पॉट पहचान तथा फोकस्ड पुलिसिंग प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। कुछ जिलों में इन प्रयासों से दुर्घटनाओं में दस से पंद्रह प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी कार्यान्वयन में एकरूपता तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच की कमी चुनौती बनी हुई है।

साहित्य तथा वर्तमान आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि मानवीय व्यवहार, अवसंरचना तथा तकनीकी हस्तक्षेपों पर एक साथ ध्यान दिया जाए तो सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। अन्य राज्यों जैसे गुजरात तथा राजस्थान के सफल मॉडल इस बात के प्रमाण हैं कि सुसंगत तथा दीर्घकालिक प्रयासों से परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

## निष्कर्ष तथा सिफारिशें ( conclusion and suggestions)

यह अनुभवजन्य अध्ययन उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों तथा उनके निराकरण की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में दुर्घटनाएँ तथा मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है तथा मानवीय त्रुटियाँ, अवसंरचना की कमी तथा पर्यावरणीय कारक इस समस्या के मुख्य आधार हैं।

अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि सड़क दुर्घटनाएँ पूर्ण रूप से समाप्त नहीं की जा सकतीं, किंतु बहुआयामी तथा समन्वित उपाय अपनाकर इनमें काफी हद तक कमी अवश्य लाई जा सकती है। यदि उचित नीतियाँ, सख्त प्रवर्तन, जन जागरूकता तथा तकनीकी नवाचारों को एक साथ लागू किया जाए तो अगले पाँच वर्षों में दुर्घटनाओं तथा मौतों में कम से कम पचास प्रतिशत तक की कमी संभव है।

## प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. राज्य स्तर पर एक व्यापक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार किया जाए तथा इसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर हॉटस्पॉट की पहचान तथा पूर्वानुमान मॉडल विकसित किए जाएँ।
3. स्कूल, कॉलेज, कार्यालय तथा सामुदायिक स्तर पर निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जाएँ जिसमें सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट तथा सीट बेल्ट के उपयोग पर विशेष बल दिया जाए।
4. सड़क अवसंरचना में सुधार किया जाए जिसमें स्पीड ब्रेकर, बेहतर साइनेज, स्ट्रीट लाइटिंग, फुटपाथ, फेंसिंग तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण शामिल हो।
5. पुलिस तथा परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए तथा स्वचालित चालान तथा स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम का पूर्ण विस्तार किया जाए।
6. दोपहिया वाहनों तथा पैदल यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा उपाय अपनाए जाएँ क्योंकि ये समूह सबसे अधिक प्रभावित हैं।

# The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 1 (January-March 2026)

इन सिफारिशों का प्रभावी क्रियान्वयन न केवल हजारों जीवन बचा सकता है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले भारी बोझ को भी कम कर सकता है। सड़क सुरक्षा को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मानकर दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आवश्यक है।

## संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय. (2022). *भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2022*. भारत सरकार. [https://morth.nic.in/sites/default/files/RA\\_2022\\_30\\_Oct.pdf](https://morth.nic.in/sites/default/files/RA_2022_30_Oct.pdf)
2. गुरराज, जी. (2008). भारत में सड़क यातायात मृत्यु, चोटें एवं विकलांगता: वर्तमान परिदृश्य. *द नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया*, 21(1), 14-20.
3. जैसवाल, के., कुमार, एस., सांत, एस. के., सिंह, ए. के., कुमार, ए., एवं सिंह, ए. (2015). केंद्रीय उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अस्पताल में सड़क दुर्घटना मामलों की चोटों का स्वरूप. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस एंड पब्लिक हेल्थ*, 4(10), 1347-1350. <https://doi.org/10.5455/ijmsph.2015.09042016341>
4. मोहन, डी., तिवारी, जी., एवं भल्ला, के. (2018). *भारत में सड़क सुरक्षा: स्थिति रिपोर्ट*. ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन प्रोग्राम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली.
5. सिंह, पी., गुप्ता, एस. सी., कौशल, एम., एवं सिंह, जी. (2015). पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना मामलों का समय एवं लिंग वितरण अध्ययन. *नेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन*, 6(3), 354-357.
6. विश्व स्वास्थ्य संगठन. (2023). *सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023*. विश्व स्वास्थ्य संगठन. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>
7. एशियाई विकास बैंक. (2012). *क्षेत्रीय मूल्यांकन (सार): परिवहन (गैर-शहरी सड़क परिवहन)*. एशियाई विकास बैंक. <https://www.adb.org/sites/default/files/linked-documents/43574-025-ssa.pdf>
8. वर्मा, पी. के., एवं गुप्ता, एस. (2018). यातायात पुलिस अभिलेखों में सड़क दुर्घटनाओं की कम रिपोर्टिंग: उत्तर भारत से एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ*, 5(2), 475-479. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20180206>
9. झा, एन., श्रीनिवास, डी. के., राँय, जी., एवं जगदीश, एस. (2004). सड़क दुर्घटना मामलों का महामारी विज्ञान अध्ययन: दक्षिण भारत से एक अध्ययन. *इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन*, 29(1), 20-24.
10. सेव लाइफ फाउंडेशन. (2023). *भारत में सड़क सुरक्षा: स्थिति रिपोर्ट 2023*. सेव लाइफ फाउंडेशन. [https://savelifefoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/v2/states/Case%20Study\\_Uttar%20Pradesh\\_Road%20Safety%20Good%20Practices%20in%20India.pdf](https://savelifefoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/v2/states/Case%20Study_Uttar%20Pradesh_Road%20Safety%20Good%20Practices%20in%20India.pdf)

# The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 1 (January-March 2026)

11. फ़ेयाज़, डी., अमीन, यू., एवं परवीन, ए. (2024). सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम संबंधी ज्ञान: कश्मीर, भारत में एक क्रॉस-सेक्शनल अध्ययन. *द एविडेंस*, 2(2).  
<https://doi.org/10.61505/evidence.2024.2.2.41>
12. मंडल, पी., दलेला, एस., बालासुब्रमणियन, एन., शर्मा, जी., एवं सिंह, आर. (2008). *सड़क दुर्घटनाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण तथा भारतीय महानगर में गीली सड़क स्थितियों पर एक केस अध्ययन* (SAE तकनीकी पत्र). SAE इंटरनेशनल.
13. हिंदुस्तान टाइम्स. (2025, 30 दिसंबर). दुर्घटना मौतों में वृद्धि के बीच 2025 उत्तर प्रदेश की सड़कों पर हाल के वर्षों का सबसे घातक वर्ष हो सकता है. *हिंदुस्तान टाइम्स*.  
<https://www.hindustantimes.com/cities/lucknow-news/amid-surge-in-mishap-deaths-2025-may-turn-out-to-be-deadliest-year-on-uttar-pradesh-roads-in-recent-past-101767037542670.html>
14. एनडीटीवी. (2025, 25 मई). उत्तर प्रदेश में 2025 में 13,000 से अधिक सड़क दुर्घटनाएँ, लगभग 7,700 मौतें. *एनडीटीवी*. <https://www.ndtv.com/india-news/up-reports-over-13-000-road-accidents-nearly-7-700-deaths-in-2025-8502192>
15. स्टैटिस्टा. (2025, 29 नवंबर). *उत्तर प्रदेश, भारत में 2014 से 2022 के बीच सड़क दुर्घटनाओं की संख्या*. स्टैटिस्टा.  
<https://www.statista.com/statistics/1084306/india-road-accidents-in-uttar-pradesh/>
16. प्रेस सूचना ब्यूरो. (2024, 24 जुलाई). भारत में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतें. *भारत सरकार*.  
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2036268>
17. टाइम्स ऑफ इंडिया. (2025, 6 नवंबर). सड़क पर जान बचाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की रणनीति. *द टाइम्स ऑफ इंडिया*.  
<https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/up-police-strategy-to-help-save-lives-on-road/articleshow/125116928.cms>
18. इंडियन एक्सप्रेस. (2025, 8 दिसंबर). सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाएँ कम करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की मेगा योजना. *द इंडियन एक्सप्रेस*.  
<https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/up-govt-unveils-mega-plan-to-boost-road-safety-and-reduce-accidents-check-the-details-10409300/>
19. 360इन्फो. (2024, 25 नवंबर). कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारतीय सड़कों पर जान कैसे बचा सकती है. *360इन्फो*. <https://360info.org/how-ai-can-save-lives-on-indian-roads/>
20. सिटिजन एडवोकेसी ग्रुप. (2025, 16 जुलाई). व्यापक सड़क सुरक्षा कार्य योजना ही समाधान क्यों है. *सिटिजन एडवोकेसी ग्रुप*. <https://www.cag.org.in/blogs/why-comprehensive-road-safety-action-plan-solution>